

प्रेषक,

विभा पुरी दास  
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त  
वन एवं ग्राम्य विकास  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. निदेशक, जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर।
3. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चौबटिया।
4. निबंधक, सहकारिता विभाग, देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग

देहरादून, दिनांक: 18 दिसम्बर, 2006

विषय: सहकारिता विभाग के अधीन संचालित भेषज विकास योजना (सहकारी जड़ी-बूटी योजना) एवं जनपदीय भेषज संघ (भेषज विकास एवं जड़ी-बूटी योजना) को उद्यान विभाग में अधीन समाहित किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय आदेश संख्या 1742/XVI/05/5(123)/2005 दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 (संलग्न-1) द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा यथा आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कर ली जाय।

1-सहकारिता विभाग के अधीन संचालित भेषज विकास योजना (सहकारी जड़ी-बूटी योजना) को उद्यान विभाग में हस्तान्तरण के फलस्वरूप योजना का संचालन भेषज विकास इकाई के रूप में किया जायेगा। यह इकाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नियंत्रण में होगी। निदेशक, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर/अपर सचिव, जड़ी बूटी इस इकाई के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किये गये हैं।

2-सहकारिता विभाग में भेषज विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पदों सहित सभी कार्यरत कर्मिकों को तात्कालिक प्रभाव से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण में लिया जाय।

3-समाहित कर्मिकों के देयको/पावकों से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकार कोषागार, देहरादून में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रदान किया जायेगा। तदनुसार आहरण वितरण कोड आवंटन करने के निमित्त प्रस्ताव वित्त विभाग को यथा शीघ्र प्रस्तुत किया जाय।

4-समाहित राजकीय कर्मिकों की सेवा शर्तें यथा सहकारिता विभाग के अनुरूप कार्यकारी रहेंगी। भेषज विकास इकाई की नियमावली गठित होने तक सहकारिता विभाग के कार्यकारी आदेशों के अनुरूप उद्यान विभाग के स्तर पर भी कार्यकारी आदेश निर्गत किये जायेंगे, तदनुरूप उनकी सेवा शर्तें व्यवहृत की जायेंगी। श्रेणी-4 तथा श्रेणी-3 कर्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे तथा श्रेणी-2 एवं श्रेणी-1 के नियुक्ति प्राधिकारी सचिव, उद्यान होंगे। तत्सम्बन्धी कार्यकारी आदेश उद्यान विभाग द्वारा यथा समय निर्गत किये जाय।

5-सहकारिता विभाग तथा उद्यान विभाग के आय व्ययक पृथक-पृथक अनुदान संख्या के अन्तर्गत व्यवहृत होते हैं, चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में सहकारिता विभाग के आय-व्ययक अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत 04-सहकारी जड़ी-बूटी योजना के विभिन्न सुसंगत मदों में कुल रु0-169.62 लाख का प्राविधान आयोजनेत्तर पक्ष में पूर्ववत् किया गया है। अतः चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 की अवशेष अवधि हेतु हस्तान्तरित कार्मिकों के वेतन-भत्तों का आहरण यथा प्रक्रिया सहकारिता विभाग के आय-व्ययक में उक्त योजना हेतु प्राविधानित वित्तीय व्यवस्था से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/भुगतान बिलों के आधार पर किया जायेगा, तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2007-08 से इस हेतु उद्यान विभाग के आय-व्ययक में आयोजनेत्तर पक्ष में यथा आवश्यक वित्तीय प्राविधान कर लिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त सहकारिता विभाग के आय-व्ययक अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत भेषज विकास एवं जड़ी-बूटी योजना (जिला योजना) में 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद में कुल रु0 21.34 लाख का वित्तीय प्राविधान आयोजनागत पक्ष में किया गया है। भेषज संघों का प्रशासनिक वित्तीय नियंत्रण एवं निबन्धन का अधिकार भेषज विकास इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रदान किये जाने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि हेतु सहकारिता विभाग के स्तर से ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रस्तावों के आधार पर भेषज संघों को अनुदान दिये जाने की कार्यवाही सहकारिता विभाग द्वारा की जायेगी एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु भेषज संघों को दी जाने वाली शासकीय अनुदान जिला-योजना के अन्तर्गत दिये जाने हेतु उद्यान विभाग के आय-व्ययक अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत यथा आवश्यक वित्तीय प्राविधान हेतु नई माँग का प्रस्ताव यथा समय नियोजन/वित्त विभाग को प्रस्तुत कर दिया जाय। भेषज संघों पर निर्देशन/नियंत्रण सम्बन्धी वर्तमान में जो अधिकार निबन्धक, सहकारी समितियों को हैं, वह अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी को होगा।

6-भेषज संघों एवं उनके अन्तर्गत गठित होने वाली तत्सम्बन्धी समितियों के निबन्धन का अधिकार भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिया गया है। अतः भेषज संघों का संचालन एवं उनकी उपविधि का नियमन उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 तथा उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली, 2004 के अधीन रहते हुए यथा आवश्यक कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाय।

7-उपरोक्तानुसार हस्तान्तरण के सम्बन्ध में यदि भविष्य में कोई कार्मिकों की सेवा सम्बन्धी/विधिक/प्रशासनिक/वित्तीय समस्या उत्पन्न होती है, तो यथा स्थिति प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग की अध्यक्षता में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Committee) का गठन किया जाता है जिसके सदस्य सचिव, उद्यान एवं सचिव, सहकारिता होंगे तथा समिति द्वारा गुणावगुण के आधार पर उत्पन्न समस्या का निराकरण यथा समय कर लिया जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सभी स्तरों पर कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

विमल जी  
(विमल पुरी दास)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त



सख्या: 1756/XVI/06/5(123)/2005, तददिनांक:-

प्रतिलिपि:

- 1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/मा० सहकारिता मंत्री जी को मा० मुख्यमंत्री जी एवं मा० सहकारिता मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- निजी सचिव, मा० उद्यान मंत्री को मा० उद्यान मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 7- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, उत्तरांचल।
- 9- अपर प्रमुख वन संरक्षक, (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तरांचल, देहरादून।
- 10- निदेशक, जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर, चमोली।
- 11- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसारण विभाग, चौबटिया।
- 12- निदेशक, रेशम विकास, प्रेमनगर, देहरादून।
- 13- निदेशक, चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
- 14- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषि निर्यात विकास इकाई, देहरादून।
- 15- निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- ✓ 16- निदेशक, कृषि, देहरादून।
- 17- निबन्धक, सहकारिता, उत्तरांचल।
- 18- उप निबन्धक, डी०सी०डी०एफ०।
- 19- प्रमुख भेषज विशेषज्ञ, देहरादून।
- 20- प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, उत्तरांचल।
- 21- व्यापार कर आयुक्त, उत्तरांचल।
- 22- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उत्पल कुमार सिंह)  
सचिव